Manish Gupta Death Case: रामपुर के इस शख्स ने NHRC में की गोरखपुर के डीएम- एसएसपी की शिकायत

https://hindi.news18.com/news/uttar-pradesh/rampur-complained-against-dm-and-ssp-in-nhrc-over-manish-gupta-case-of-gorakhpur-upns-3773788.html

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर (Gorakhpur) के तारामंडल इलाके में स्थित कृष्णा पैलेस होटल में हुई कानपुर (Kanpur) के मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले में गोरखपुर के डीएम-एसएसपी और संबंधित थाना पुलिस के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार (NHRC) आयोग में शिकायत भेजी गई है. रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खां के आयोग में शिकायत के लिए प्रार्थना पत्र भेजा है. रामपुर के नादरबाग मढ़ैया निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खां ने इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा जिसमें कहा है कि गोरखपुर के इस चर्चित प्रकरण में पुलिस लीपा-पोती की कोशिश कर रही है, जबकि मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसकी झूठी कहानी की पोल खोलकर रख दी है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि मनीष के सिर, चेहरे और शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं. मनीष के सिर के अगले हिस्से पर तेज प्रहार किया गया, जिससे उनके नाक के पास से खून बह रहा था. हालांकि, पुलिस ने घटना के बाद अपने पहले बयान में इसे हादसे में हुई मौत बताया था. उन्होंने डीएम, एसएसपी और संबंधित थाना पुलिस पर कार्रवाई की मांग की.

कारोबारी की पत्नी को मिली OSD की नौकरी

इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर पुलिस लाइन में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी से मुलाकात की. सीएम ने मीनाक्षी की नौकरी, मुआवजा और गोरखपुर से कानपुर केस ट्रांसफर कराने की मांग मान ली. सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनीष गुप्ता की पत्नी को विकास प्राधिकरण में ओएसडी की नौकरी देने और राहत राशि 10 लाख से बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन से प्रस्ताव देने को कहा है. मनीष गुप्ता के परिवार ने सीबीआई जांच की भी मांग रखी. सीएम ने इस पर भी आश्वासन दिया. सीएम ने कहा कि जांच के संबंध में भी जो कुछ होगा किया जाएगा.

कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर में हुई घटना बेहद शर्मनाक है. कल ही पीड़ित परिवार से मिलने की इच्छा मैंने जताई थी. अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है. कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा. सीएम ने कहा पीड़ित परिवार जैसी जांच चाहेगा वैसी जांच सरकार करवाने को तैयार है. यदि परिवार सीबीआई जांच चाहता है तो सीबीआई को जांच

के लिए प्रेषित किया जाएगा. यदि कानपुर पुलिस द्वारा जांच चाहता है, तो कानपुर पुलिस को जांच के लिए कहा जाएगा.

यूपी: जेल भेजे गए किशोर ने कथित तौर पर ख़ुदकुशी की, एनएचआरसी ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी

http://thewirehindi.com/188351/up-minor-sent-to-jail-allegedly-ends-his-life-nhrc-seeks-report-from-police/

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मादक पदार्थ रखने के आरोप में 'बालिग के तौर पर जेल भेजे जाने के बाद' 15 वर्षीय एक किशोर के कथित तौर पर आत्महत्या कर लेने के एक हालिया मामले में उत्तर प्रदेश की एटा जिला पुलिस से रिपोर्ट मांगी है.

इसके अलावा, आयोग ने अपने जांच विभाग को मौके पर जाकर मामले की जांच करने का भी निर्देश दिया है.

एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि उसने एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को सीनियर रैंक के एक पुलिस अधिकारी द्वारा आरोपों की जांच करने और चार सप्ताह के भीतर आयोग को कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

आयोग ने कहा कि उसने 'अख़बार में प्रकाशित समाचार की एक क्लिपिंग के साथ इस शिकायत का संज्ञान लिया है कि 15 वर्षीय एक किशोर मादक पदार्थ रखने के आरोप में एक वयस्क के रूप में जेल भेजे जाने की यातना को सहन नहीं कर सका. उसने तीन महीने बाद जमानत पर रिहा होने के बाद 21 सितंबर को उत्तर प्रदेश के एटा में आत्महत्या कर ली.'

इसमें कहा गया है कि कथित तौर पर किशोर को एटा पुलिस ने 'नशीली दवाएं रखने के संबंध में गिरफ्तार किया था और उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करने के बजाय जिला जेल भेज दिया गया.

इसने कहा कि किशोर के पिता ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि उसके बेटे को 'अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया था और पुलिस द्वारा पैसे वसूलने के लिए प्रताड़ित' किया गया था.

एनएचआरसी ने एसएसपी को पुलिस द्वारा आरोपी की उम्र और जन्मतिथि का आकलन करने के लिए किस प्रोटोकॉल का पालन किया गया, जैसे कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है.

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (जेजे अधिनियम) के नियम 7 और धारा 94 (सी) के अनुसार, जन्म तिथि उम्र का प्राथमिक प्रमाण है. आयोग ने पुलिस से सवाल किया है कि किन परिस्थितियों में उक्त किशोर के साथ बालिग जैसा व्यवहार किया गया.

बयान में कहा गया कि आयोग ने अपने जांच विभाग को मौके पर जाकर जांच करने, मामले का विश्लेषण करने और संस्थागत उपाय सुझाने का निर्देश दिया है, जिसकी सिफारिश सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए की जा सकती है कि अभियोजन के लिए बच्चों के साथ वयस्कों जैसा व्यवहार नहीं किया जाए.

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, आयोग ने उन जज, जिनके सामने इस नाबालिग को गिरफ़्तारी के चौबीस घंटों के अंदर पेश किया गया और जिस चिकित्सक ने उसकी जांच की, समेत मामले के सभी हितधारकों की भूमिका जांचने का निर्देश भी दिया है.

जांच विभाग को छह सप्ताह के भीतर इसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है.

TV9 EXCLUSIVE: हिरासत में मौत (पार्ट-1)- सजा की बात छोड़िए मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें, निर्देश तक पड़े 'सिसक' रहे हैं!

https://www.tv9hindi.com/crime/custodial-death-human-rights-commission-police-custody-death-in-india-manish-gupta-case-847741.html

हिंदुस्तान के किसी थाने चौकी या फिर किसी भी राज्य की पुलिस हिरासत में फंसा जब-जब कोई बेकसूर-असहाय 'बेमौत' मार डाला जाता है. तब-तब देश का राष्ट्रीय मानवाधिकार और कानून कराहने लगता है. तब तक जितने दिन मरने वाले की मौत पर कोहराम सुनाई देता है. उतने ही दिन इन मौतों को रोकने के लिए गठित तमाम एजेंसियों, संगठनों, आयोगों की 'चहलकदमी' से सरकारी फाइलों में होने वाली आहट सुनाई देती है. मरने वाले की मौत के ग़म के साथ ही धीरे-धीरे सब कुछ पहले जैसा रमने-बहने लगता है. इसकी गवाह देश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Right Commission) की सैकड़ों 'सुस्त' पड़ी सिफारिशें ऐसी हर मौत के बाद कुछ दिन तक चीख-चीख देती हैं.

ऐसा नहीं है कि न्यायिक और पुलिस हिरासत में मौत के मामलों पर अंकुश के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत ने उपाय नहीं किए हैं. उपाए तो इतने ज्यादा किए हैं कि आम या फिर पीड़ित उन उपायों की गिनती करते करते थक जाए. यह अलग बात है कि यह तमाम उपाय सिर्फ और सिर्फ हर ऐसी 'अकाल-मौत' के बाद ही, कुछ दिन हलचल करके फिर फाइलों में दफन हो जाते हैं या कहिए जान-बूझकर दफना दिये जाते हैं. थाने-चौकी में फिर ऐसी ही किसी असहाय पीड़ित की खौफनाक अकाल मौत का मामला सामने आने तक. कहने को तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यहां तक राज्य सरकारों और केंद्र शासित राज्यों को हिदायतें दे रखी हैं कि, "पुलिस या न्यायिक हिरासत में हुई मौत के मामलों की सूचना वे तत्काल आयोग के संज्ञान में लाएं." सवाल फिर वही कि क्या ऐसा होता भी है?

राष्ट्रीय मानवाधिकार का अपना दु:ख

क्या NHRC के इन सब दिशा-निर्देशों के बाद ऐसा होता भी है? इस सवाल का जबाब खुद NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) के फाइलों में धूल फांक रहे भारी-भरकम फरमान ही देते हैं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी अंतिम वार्षिक रिपोर्ट (इसके बाद अभी तक एनएचआरसी की शायद कोई सालाना नई रिपोर्ट जारी नहीं हुई है) 2017-2018 की संसद में पेश की थी. उस भारी भरकम वजनदार रिपोर्ट में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिरासत में मौत के मामलों को दो श्रेणियों में बांटने की बात कही. पहली श्रेणी में न्यायिक हिरासत में हुई मौत के मामले. दूसरी श्रेणी में पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामलों का लेखा-जोखा दर्ज किए जाने का उल्लेख है. रिपोर्ट में एक जगह खुद आयोग ने उल्लेख किया है कि,

NHRC जो महसूस करता है

“देश में हिरासतीय हिंसा और प्रताड़ना अनियंत्रित रूप से जारी है. यह उन लोक सेवकों, जिनके ऊपर कानून को लागू करने की जिम्मेवारी है, के द्वारा की जाने वाले ज्यादती के भयावह रूप को प्रस्तुत करता है. आयोग ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रतिबध है. पीड़ितों अथवा उनके निकट संबंधी को मुआवजे की सिफारिश के अतिरिक्त आयोग का प्रयास उस माहौल को खत्म करने की दिशा में भी जारी है, जिसमें पुलिस वाले, हिरासत एवं जेल की चार-दीवारी के अंदर, जहां पीड़ित असहाय होता है, को ‘यूनिफार्म’ व ‘अधिकार’ की आड़ तले मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं.”

लिखा-पढ़ी में कमी नहीं मगर रिजल्ट....

ऐसे में सवाल फिर वही कि अगर आयोग इतना सबकुछ लिख पढ़ रहा है. आयोग की जिम्मेदारी है इस तरह की निरंकुश होते जा रहे पुलिस वालों पर अंकुश लगाने की. आयोग को न्यायिक कदम उठाने की ताकत भी हुकूमत ने बख्शी हुई है. तो भी आखिर देश में हर साल न्यायिक और पुलिस हिरासत में मौतों का आंकड़ा नीचे आने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? या यह भी कहा जा सकता है कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए गठित या तो कहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कमजोर पड़ रहा है. या फिर बेकसूरों को हिरासत में अकाल मौत सुलाने की जिद पर उतरी बेखौफ खाकी, जाल में फंसे निरीह इंसानों के साथ साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ऊपर भी भारी साबित होता जा रहा है. संसद में पेश इसी रिपोर्ट में एक जगह आयोग आगे लिखता है.....

NHRC को बरगलाने से भी बाज नहीं आते कुछ राज्य

“हिरासत में होने वाली मौत की सूचना 24 घंटे के भीतर आयोग तक पहुंचाए जाने के दिशा-निर्देश मौजूद हैं. इसके बाद भी अक्सर देखने में यही आता है कि कुछ मौतों की सूचना काफी विलंब से की जाती है. जबकि कई मामलों में ं तो संबंधित प्राधिकारियों को सशर्त समन जारी करने के बाद ही आयोग को ऐसी मौतों से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है.”

देश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कि उस रिपोर्ट में दर्ज ऊपर उल्लिखित यह चंद लाइनें इस बात की तस्दीक करती हैं, जोकि भारत की संसद में पेश की जा चुकी है कि, पुलिस या न्यायिक हिरासत में हुई मौत के मामलों की खबर निर्धारित अवधि के अंदर संबंधि राज्य नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को देने के लिए तक राजी नहीं है. बदहाली का यह आलम तो उस आयोग का है जिसे हिंदुस्तानी हुकूमत ने इन खौफनाक मौतों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी सौंपी है है.

कारोबारी की मौत के मामले में ''खुद को बचा रही है'' उत्तर प्रदेश सरकार : अखिलेश

https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/lucknow/other-news/in-the-case-of-businessmans-death-uttar-pradesh-government-is-protecting-itself-akhilesh/articleshow/86678312.cms

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ''खुद को बचा रही है'' और इस मामले से रंगदारी का एक रैकेट जुड़ा है।

यादव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार दोषी अधिकारियों को बचा रही है, क्योंकि इन अधिकारियों ने उन्हें चुनाव जितवाया है और गोरखपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता के रिश्तेदार हैं।

यादव ने ट्वीट किया, '''मनीष गुप्ता हत्याकांड' में पुलिसवालों की गिरफ्तारी नहीं होना ये दर्शाता है कि वो फरार नहीं हुए हैं उन्हें फरार कराया गया है। दरअसल कोई आरोपियों को नहीं बल्कि खुद को बचा रहा है क्योंकि इसके तार 'वसूली-तंत्र' से जुड़े होने की पूरी आशंका है। 'जीरो टालरेंस' भी भाजपाई जुमला है।''

गौरतलब है कि सोमवार देर रात को गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल इलाके में पुलिस ने एक होटल में तलाशी ली थी। आरोप है कि किसी अन्य व्यक्ति के पहचान पत्र के आधार पर होटल के एक कमरे में रुके तीन व्यवसायियों से पूछताछ के दौरान पुलिस ने उन्हें मारा पीटा था। सिर में चोट लगने से उनमें से मनीष गुप्ता (36) नामक कारोबारी की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी।

मामले में आरोपी सभी छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। घटना के वक्त गुप्ता अपने दो दोस्तों के साथ होटल में ठहरे हुए थे।

यादव ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''जब राज्य सरकार उनसे (अधिकारियों से) गलत काम करवायेगी और प्रशासन चुनाव जितवाने का काम करेगा तो इनकी गलतियों को कौन छिपायेगा? जाहिर है, राज्य सरकार छिपायेगी। उनकी गलती इसलिये छिपायी जा रही है क्योंकि उनसे (अधिकारियों से) चुनाव जीतने के लिये मदद ली गयी थी।''

यादव से जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए उस वीडियो के बारे में पूछा गया जिसमें कारोबारी के परिवार को प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने के लिए मनाया जा रहा है, तो सपा अध्यक्ष ने कहा,

''क्या वहां के एक पुलिस अधिकारी (गोरखपुर के एसपी) भाजपा के एक नेता के रिश्तेदार नहीं है? पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई इसलिये नहीं हो रही है क्योंकि वह भाजपा नेता के रिश्तेदार हैं। जब प्रशासन से भाजपा चुनाव जितवाने में मदद लेगी तो उनसे (भाजपा नेताओं से) कैसे उम्मीद कर सकते हो कि न्याय मिलेगा?''

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस अत्याचार की यह घटना पहली नहीं है, इससे पहले लखनऊ, झांसी, नोएडा और राज्य के अन्य हिस्सों में ऐसी घटनायें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, ''राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य को सबसे ज्यादा नोटिस भेजे हैं।''

कारोबारी की मौत के मामलें में गोरखपुर में फरार छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। यादव ने पूछा कि 'दमदार' सरकार इन फरार पुलिसकर्मियों के मकानों पर अब बुलडोजर क्यों नहीं चला रही है। उन्होंने आरोप लगाया, ''राज्य में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) का एक अधिकारी भी फरार है, ऐसे लोगों को राज्य सरकार ने फरार करवाया है और उनकी मदद कर रही है।''

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के बारे में पूछे जाने पर, यादव ने कहा, ''इसे (पेट्रोल,डीजल को) जीएसटी के तहत क्यों नहीं लाया गया, जबकि जीएसटी परिषद में भाजपा के पास बहुमत है क्योंकि राज्यों में उसकी सरकारें हैं। फिर वे निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं।''

चुनाव में मतपत्र के इस्तेमाल के बारे में यादव ने कहा, ''सपा सरकार लाओ, ईवीएम हटाओ।'' उन्होंने कहा, ''पंचायत चुनाव में मतपत्रों का उपयोग हुआ था और सपा ने अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की थी। अमेरिका में भी मतपत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है।''

2022 के राज्य विधानसभा चुनावों के बारे में यादव ने कहा कि यह सपा की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह देश और संविधान को बचाने की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने को तैयार है, साथ ही जनता, किसान, नौजवान भी तैयार हैं।

पंजाब की राजनीति के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा, ''सुनने में आया हैं कि पंजाब में भी भाजपा ने झगड़ा लगाया है, वह कुछ भी कर सकती है।''

UP: NHRC Sets up Inquiry in Minor Boy's Death by Suicide After Spending 3 Months in Jail

https://www.newsclick.in/UP-NHRC-inquiry-minor-boy-death-suicide-spending-3-months-jail

The National Human Rights Commission (NHRC) has instituted inquiry into death by suicide of a minor boy who was sent to district jail on charges of possession of drugs. The Commission has taken cognisance of a complaint it received that a 15-year-old boy unable to bear the torture of being sent to a jail as an adult on charges of drug possession, committed suicide when released on bail after three months in Etah, Uttar Pradesh on September 21. The father of the boy has reportedly alleged that his son was illegally arrested and tortured to extort money by the police.

The Commission has directed the SSP, Etah to have the allegations inquired by a Senior Rank Police Officer, and submit an action taken report to the Commission, within four weeks.

The NHRC has sought the following information in the report:

1. As per rule 7 of the JJ Act and section 94 (c) of the JJ Act, Date of birth is the primary proof of age; therefore, under what circumstances, the Juvenile was treated as an adult.

2. Non-consideration of the matriculation certificate as proof of the DOB is in violation of judgment in the matter of "Ashwani Kumar Saxena vs. State of MP (2012) 9 SCC 750"; therefore, under what circumstances this was ignored.

3. What protocol is being followed for assessing the age and date of birth of the accused by police?

The Supreme Court in Ashwani Kumar Saxena vs. State of MP (2012) 9 SCC 750 had highlighted the provisions of the Juvenile Justice Act which stipulates that an age determination inquiry be carried out under section 7A of the Act. This provision requires the court to obtain the matriculation or equivalent certificates and in absence of that obtain the date of birth certificate from the school first attended. “Once the court, following the above mentioned procedures, passes an order; that order shall be the conclusive proof of the age as regards such child or juvenile in conflict with law. It has been made clear in subsection (5) or Rule 12 that no further inquiry shall be conducted by the court or the Board after examining and obtaining the certificate or any other documentary proof,” the court has said.

The Commission has thus cited this case to understand whether this process was followed by the court that remanded him to custody. Interestingly, the Commission has also sought to know what protocol does the police follow to determine the age of a suspect who claims to be a minor or is visibly a minor.

There are provisions for that as well under section 12 of the Juvenile Justice Act which states that when any person, who is apparently a child and is alleged to have committed

a bailable or non-bailable offence, is apprehended or detained by the police such person shall be released on bail with or without surety or placed under the supervision of a probation officer or under the care of any fit person.

Alternatively, if such a person is not released on bail due to exceptions, then the officer in charge is required to place such person in an observation home until the person (apparently a child) can be brought before a Juvenile Justice Board. Neither of these procedures seemed to have been followed by the police in this case, despite the boy or his family making claims of his juvenility.

The Commissions has also directed its Investigation Division to conduct an on the spot enquiry, analyze the case and suggest the institutional measures, which could be recommended to the government to ensure that the children are not being treated as adults for prosecution.

The Investigation Division has also been directed to look into the role played by all the concerned stakeholders in this case, including the Judge, before whom the child was produced within 24 hours of the arrest, and the role of the doctor who examined the child. This report is expected in 6 weeks.

The boy was arrested by the police on March 9 and his father stated that he had ventured out to buy pizza and was arrested. The police had said that they found 500g diazepam on him and his father alleges that he was kept in lockup and beaten up by the police for 4 days while the cops demanded Rs. 2 lakh to release him.

He was then produced before the court as an adult and was remanded to custody under the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act on March 12. He had to spend 3 months in jail before his parents managed to secure bail for him on July 25 on the grounds that the police had not filed a chargesheet.

After he returned home, his parents said he seemed changed and was not the cheerful teenager he always was. The father has filed a complaint for abetment of suicide against sub-inspectors Mohit Rana and Shiv Kumar, head constable Upendra Kumar and constable Ravish Kumar.

Man comes in touch with live wire, dies

https://www.dailypioneer.com/2021/state-editions/man-comes-in-touch---with-live-wire--dies.html

Milap Thela, a resident of Khairbhadi village under Tukula gram panchayat of Khariar block, died on the way to his farmland when he came in contact of a live electric wire lying on ground on Friday.

The villagers reported the incident to the electricity department and departmental personnel along with police arrived at the scene and ascertained that the accident occurred due to the live wire that had fallen from the electric pole.

Family members of Milap were assured of compensation by officials. The Sarpanch of Tulkula panchayat provided an assistance of Rs 2,000 to the deceased’s family under the Harishchandra Yojana. Officials also promised to provide financial support from the Red Cross.Milap has two small children and wife.People are aggrieved that the electricity department did not pay compensation suo motu in earlier such cases.

"The department has not paid compensation to the family members of one Bhupendra Majhi of Kirkita village under Khariar block who died two years ago coming in contact of a live wire on road in spite of direction from the NHRC. There is no proper maintenance of wires, which are very old. Such incidents are occurring due to lack of maintenance and vigilance.

This is criminal negligence on the part of electricity department. It is a clear case of violation of human rights of the deceased. Therefore, the concerned families should be compensated immediately," said Fakira Jagat of Tulla.

Akhilesh slams UP govt, says BJP main culprit behind collapse of law and order

https://www.aninews.in/news/national/politics/akhilesh-slams-up-govt-says-bjp-main-culprit-behind-collapse-of-law-and-order20211001232509

Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav on Thursday targeted the Uttar Pradesh government over the death of a businessman during a police raid in a hotel room in Gorakhpur and alleged that BJP is the main culprit behind the collapse of law and order in the state. "How will BJP hide the assassination of the businessman who was killed by the police? Even the postmortem is out now. BJP talks about zero tolerance for crime. But whatever happened in Gorakhpur, it has never happened anywhere in this world," Yadav said. Manish Gupta was Kanpur based businessman, who died on Monday after a police raid in a Gorakhpur hotel in which he got injured and later succumbed to his injuries. The family of the Kanpur-based businessman has alleged that he was beaten to death by police during the raid at the hotel. Yadav alleged that BJP deliberately let the corrupt policemen escape and it was the main culprit behind the collapse of law and order in the state. "BJP can not punish the corrupt officials because these officials help them win elections. It was our workers who won the most during the Zila Panchayat elections but the results in end came out in favour of the BJP. BJP is the main culprit for the collapsing law and order in the state. There are officers, officials who want to serve justice, but can not do so due to BJP pressurising them into not serving justice," he said.

He said that it was under the BJP government in the state that the most number of custodial deaths, encounters are being recorded. "National Human Rights Commission has sent the most number of notices to the UP government," he added. Attacking the BJP, he said that the party did not promise welfare to anyone. "Under BJP, there is no welfare for farmers, youth, businessmen. There is no employment. There is a severe price rise and injustice against all. But BJP does not know anything about it. Farmers can't get the prices for their crops. The rights of everybody are being curtailed. Nobody lies more than BJP," he said. Asserting that Samajwadi Party will win the elections and people were ready to remove BJP from power, he said, "Everyone wants to remove BJP because they see through its lies and deception. The inaugurations done by the government of various services are nothing but lies. Dalits, farmers, youth and everyone in the state is ready to throw out BJP from power. Samajwadi Party will form the government and take the state and the nation forward while walking on the path of Ambedkar and Ram Manohar Lohia, of the constitution." Elections for 403 assembly constituencies in Uttar Pradesh are due early next year. Yadav said that his party believed that the caste census should happen. (ANI)

Extortion racket link behind killing of Kanpur businessman: Akhilesh Yadav

https://www.outlookindia.com/newsscroll/extortion-racket-link-behind-killing-of-kanpur-businessman-akhilesh-yadav/2170850

Samajwadi Party president Akhilesh Yadav on Friday attacked the Uttar Pradesh government over the death of a Kanpur businessman in a police raid, claiming that the case is linked to an extortion racket and "someone" is trying to save himself.

Businessman Manish Gupta died in a Gorakhpur hotel during the raid late on Monday night, prompting authorities to suspend six policemen and book them for murder. The policemen are absconding.

"No policeman has been arrested in the Manish Gupta murder case. This shows that they did not escape themselves but were made to escape. Actually, someone is not saving the accused but saving himself as its strings are linked to the "vasooli tantra" (extortion racket)," Yadav said in a tweet in Hindi.

""Zero-tolerance" is also a BJP jumla (rhetoric)," he said, in an apparent reference to Chief Minister Yogi Adityanath"s assertion that the state has zero-tolerance towards crime and corruption.

Referring to the incidents of violence during the panchayat elections, Yadav told a press conference that as the BJP had used officials of the administration during the polls for "political reasons", its government is now defending them.

"A top official posted in Gorakhpur is relative of a BJP leader," he said when asked about a viral video in which the Gorakhpur district magistrate and senior superintendent of police are seen allegedly pressuring Gupta"s family not to lodge an FIR.

"When you use the administration"s officials for political reasons, how can you take action against them when they do anything wrong," Yadav said.

He said this is not the first incident of police atrocity. Earlier, such incidents have taken place in Lucknow, Jhansi and other parts of the state, the Samajwadi Party (SP) leader said.

"The National Human Rights Commission has served maximum number of notices to the state," he said

On the accused policemen being at large, Yadav said why is this "damdar" (strong) government not apprehending these policemen.

"An IPS is also absconding in the state. Such people have been made to abscond by the government, which is helping them," he alleged.

On being asked about the rise in petrol and diesel prices, Yadav said, "Why are they not being brought under the Goods and Services Tax (GST). The BJP has majority in the GST Council as it has governments in states. Why it is not taking a decision."

About use of ballot in elections, Yadav said, "Bring a SP government, and remove electronic voting machines."

"The panchyat polls were held using ballot papers and SP won the majority of seats. In the US also ballot paper is being used," he said.

On the 2022 assembly polls, Yadav said that it is not the just the fight of the SP but "it is the fight to save the country and the Constitution", adding that BJP was humiliating all the sections of society by its behaviour.

He said that even good officers in the state cannot work in the present regime and they were "forced to lie" under government pressure. PTI ABN ANB

Arif scooped up soil and hurled it at cops: Witness

https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/arif-scooped-up-soil-and-hurled-it-at-cops-witness/articleshow/86691474.cms

Additional revenue inspector Abdul Rauf who was one of the two non-police eye-witnesses of the alleged encounter, was examined by the commission's advocate on Friday. Rauf is one of the panchnama witnesses who accompanied the police team and the four accused from the safe house in Mirzaguda to Chattanpally encounter site to recover the articles of Disha buried in the fields on December 6, 2019. Rauf stated that while pointing to the spot at the fifth embankment in the field where Disha's articles were buried by the accused, Md Arif, gathered soil with both his hands and flung it in the eyes of the cops and panch witnesses standing nearby. Rauf went on to add that while CI Narasimha Reddy was cleaning his eyes, Arif snatched his firearm and ran.

The witness also stated that while wiping his eyes, from the corner of one eye, he saw that one of the accused assaulting a cop with sticks and stones at the embankment. However, Rauf also said that he could not identify who exactly was the attacker and the cop.

When the commission's advocate pointed to Rauf that he did not mention about Arif scooping up soil and throwing it in the faces of police personnel before the judicial magistrate in his statement recorded under Section 164 of the CrPC, Rauf stated that, "I had stated before the magistrate, but she did not record it. I had pointed it to her, but she admonished me and I signed out of fear as the magistrate sternly asked me to sign." When it was again pointed out to him that even in his statements recorded by investigating officer (IO) J Surender Reddy and NHRC team, there was no mention of Arif throwing soil at police, the witness maintained that he had mentioned it and did not know whether it was recorded or not. Abdul Rauf stated that while pointing to the spot where Disha's articles were buried, Arif gathered soil and flung it in the eyes of the cops. He also stated that while CI was cleaning his eyes, Arif snatched his firearm and ran.

Hyderabad rape case: No injuries sustained by accused due to custodial torture, says medico

https://www.newindianexpress.com/cities/hyderabad/2021/oct/01/hyderabad-rape-case-no-injuries-sustained-by-accused-due-to-custodial-torture-says-medico-2366205.html

Dr T Krupal Singh, professor and HOD of Forensic Medicine and Toxicology at Gandhi Hospital, who led a team of doctors to conduct the first autopsy on the bodies of the four accused in the rape and murder of a veterinarian, deposed before the three-member SC commission.

During the deposition, he informed they had collected gunshot residue (GSR) using cotton swabs from Mohd Arif and Chintakunta Chennakesavulu and sent the same for forensic analysis through Shadnagar police. The swabs were collected before washing the bodies for the PME. “But, this fact has not been mentioned in the PME report as it is the procedure to be followed,” said Dr Krupal Singh. He said that his statement about collection of GSR samples was from his memory and that he had not mentioned it anywhere.

‘Cops didn’t update us on NHRC guidelines’

He also stated that the police did not inform them about the NHRC guidelines to be followed while conducting PME in custodial death cases. When the commission asked him if they had ruled out all indices of custodial torture and interrogation in the PME reports, as per NHRC guidelines, he stated: “we did not find any injuries related to torture on the bodies.” He also stated that “no abrasion injuries and no bullet grazing injuries were noted” on Mohd Arif’s body and that the injuries “were all piercing firearm injuries.”

When questioned, referring to the statement of the AIIMS team’s PME reports, Dr Krupal Singh said, “This could be an artefact, as a fresh abrasion is easily found on the day of first PME. AIIMS team conducted PME on the 17th day after the first PME and bodies were preserved at a temperature of 4-6 degrees centigrade and all bodies were dry and desiccated due to cold and abrasion at that point can not be made out” he stated.